*केंद्रीय बैंक लेखांकन पद्धतियां: भारतीय रिज़र्व बैंक और वैश्विक दृष्टिकोण**

श्री शिरीष चंद्र मुर्मू

विशिष्ट अतिथियों और मेरे साथियों, नमस्कार और सुप्रभात!

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एसईईसीईएन केंद्र के साथ संयुक्त रूप से आयोजित केंद्रीय बैंक लेखांकन प्रथाओं पर इस पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित केंद्रीय बैंकरों, प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञ वक्ताओं और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मेरे सहयोगियों की इस गरिमामयी सभा को संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे खुशी है कि केंद्रीय बैंकों में लेखांकन के विषय ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकरों की रुचि को आकर्षित किया है और 20 से अधिक देश इस आयोजन में भाग ले रहे हैं।

इस सम्मेलन का उद्देश्य, केंद्रीय बैंकों की विविध लेखांकन प्रथाओं में योगदान देना और समझना, एक-दूसरे से सीखना, विश्व स्तर पर स्वीकृत कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार-विमर्श करना और लेखांकन प्रथाओं में पारदर्शिता और स्थिरता में सुधार करना है। आज अपनी टिप्पणी में, मैं केंद्रीय बैंकों द्वारा निभाई गई अनूठी भूमिका, उनकी बैलेंस शीट के महत्व और कुछ लेखांकन प्रथाओं के बारे में संक्षेप में बात करूंगा जो केंद्रीय बैंकों के वित्तीय विवरणों को प्रभावित करते हैं। मैं केंद्रीय बैंक लेखांकन में चर्चा के कुछ उभरते क्षेत्रों पर भी बात करूंगा।

केंद्रीय बैंकों की अनूठी भूमिका

केंद्रीय बैंक दो मायनों में अद्वितीय हैं। सबसे पहले, वे सार्वजनिक नीति संस्थान हैं जो बिना किसी लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। नतीजतन, उनकी बैलेंस शीट उन नीतिगत उपायों को दर्शाती है जो वे एक निश्चित अवधि के दौरान देश की मौजूदा आर्थिक स्थितियों से निपटने करने के लिए करते हैं। दूसरा, चूंकि एक केंद्रीय बैंक के पास पैसा बनाने का विशेष अधिकार है, इसलिए यह सामान्य अर्थों में दिवालिया नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, भले ही इसकी बैलेंस शीट नुकसान या ऋणात्मक इक्विटी दिखाती हो, फिर भी यह अपने कार्यों को पूरा कर सकती है ।

केंद्रीय बैंक के अधिदेश सभी अधिकार क्षेत्रों में में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, जो उनके ऐतिहासिक और संस्थागत संदर्भों को दर्शाते हैं। देशों में अधिदेश, कार्यों या भूमिकाओं में अंतर के बावजूद, प्रत्येक केंद्रीय बैंक के केंद्र में मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता है। केंद्रीय बैंकों का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त पूंजी और आरक्षित निधि/जोखिम बफर बनाए रखना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सबसे व्यापक अधिदेश में से एक है, जो एक पूर्ण-सेवा[1] केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है जो आमतौर पर केंद्रीय बैंक से जुड़ी जिम्मेदारियों की एक विस्तृत श्रृंखला का कार्य करता है।

जब केंद्रीय बैंक पूंजीकरण की बात आती है, तो मेरा मानना है कि पर्याप्त पूंजीकरण बिल्कुल महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों के लिए। ये केंद्रीय बैंक न केवल घरेलू मौद्रिक स्थिरता लाना चाहते हैं, बल्कि अस्थिर पूंजी प्रवाह और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीति में बदलाव के प्रसार (स्पिल-ओवर) प्रभावों के बीच बाह्य क्षेत्र की स्थिरता के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अच्छी तरह से पूंजीकृत केंद्रीय बैंक किसी देश की स्थिति को ऊंचा करता है और वित्तीय क्षेत्र को आघात-सह्य बनाता है।

---

* भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री शिरीष चंद्र मुर्मू ने 14 नवंबर 2025 को मुंबई में एसईएएसईएन केंद्र के साथ संयुक्त रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित केंद्रीय बैंक लेखांकन प्रथाओं पर पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। संगीता लालवानी, व्योम गुप्ता और अक्षय वर्तक द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है।

[1] मौद्रिक नीति निर्माण, मुद्रा प्रबंधन, विनियमन और वित्तीय प्रणाली का पर्यवेक्षण, भुगतान और निपटान प्रणाली, आरक्षित निधि प्रबंधन, बैंकों और सरकारों के लिए बैंकर, सरकारों के ऋण प्रबंधक, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय बाजारों के प्रमुख क्षेत्रों जैसे मुद्रा बाजार, जी-सेक बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार, विकासात्मक कार्यों आदि का विनियमन और निरीक्षण।

केंद्रीय बैंकों के लिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जोखिम पूंजी ढांचा न होने पर, प्रत्येक केंद्रीय बैंक को केंद्रीय बैंक की पूंजी की अवसर लागत, सामाजिक-आर्थिक लागत और कम पूंजीकरण के नकारात्मक परिणामों के बीच संतुलन ढूंढना पड़ता है।

केंद्रीय बैंकों के लिए लेखांकन मानक

जैसा कि व्यापक रूप से समझा जाता है, विशेष रूप से केंद्रीय बैंकों के लिए डिज़ाइन किया गया कोई भी विश्व स्तर पर स्वीकृत लेखांकन मानक नहीं है और इसलिए, उनके लेखांकन और प्रकटीकरण प्रथाएं, प्रारूप और स्वरूप में काफी भिन्न होती हैं। जहाँ कुछ केंद्रीय बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) में निर्धारित सिद्धांतों को अपनाया है, या तो पूर्ण रूप से या अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधनों के साथ, अन्य अपने स्वयं के राष्ट्रीय लेखांकन मानकों को लागू रखते हैं या विशेष रूप से केंद्रीय बैंक के लिए तैयार किए गए हाइब्रिड ढांचे का उपयोग करते हैं।

केंद्रीय बैंकों द्वारा चुनी गई लेखांकन नीतियां उनकी बैलेंस शीट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेखांकन नीति के प्रमुख क्षेत्र जिनका केंद्रीय बैंकों की पूंजी स्थिति और आय पहचान ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उनमें शामिल हैं, (i) निवेश की पुनर्मूल्यन आवृत्ति (ii) अवास्तविक पुनर्मूल्यन लाभ/हानि का उपचार (iii) प्रावधान पद्धति/जोखिम बफर का रखरखाव और (iv) अधिशेष वितरण नीति। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी की समीक्षा से संकेत मिलता है कि इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय बैंक इन प्रमुख लेखांकन आयामों में समष्टि दृष्टिकोण का पालन करते हैं। ये विविधताएं सांविधिक अधिदेशों, संस्थागत उद्देश्यों, जोखिम प्रबंधन दर्शन और समष्टि आर्थिक संदर्भ में अंतर को दर्शाती हैं जिसके भीतर प्रत्येक केंद्रीय बैंक संचालित होता है।

आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन पद्धतियां

अब मैं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन पद्धतियों के बारे में संक्षेप में बात करना चाहता हूं। केवल एक संदर्भ दें, भारतीय रिज़र्व बैंक का संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास निहित है। जिस तरह से आरबीआई अपने वित्तीय विवरण तैयार करता है और अपनी लेखांकन नीतियां निर्धारित करता है, वह मुख्य रूप से 1934 के आरबीआई अधिनियम और 1949 के आरबीआई सामान्य विनियमों द्वारा निर्देशित होता है। समय के साथ, इस विधिक ढांचे के भीतर, ये नीतियां बदलती जरूरतों और प्रथाओं को बनाए रखने के लिए विकसित हुई हैं।

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एक मजबूत और सुदृढ़ बैलेंस शीट है, जिसमें पर्याप्त स्तर का जोखिम प्रावधान है। पिछले कुछ वर्षों में, आरबीआई ने विवेक और परंपरागत के मूल सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हुए, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अपनी लेखांकन प्रथाओं को संरेखित करने के लिए लगातार काम किया है।

मैं पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आरबीआई की लेखांकन नीति के कुछ प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा: - क) विधिक ढांचा, ख) लेखांकन में विवेक, ग) अधिशेष वियोजन नीति, घ) बैलेंस शीट की ताकत, और ई) प्रकटीकरण।

विधिक ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934[2] दो प्रमुख सिद्धांतों को निर्धारित करता है जो परिभाषित करते हैं कि आरबीआई लेखांकन के दृष्टिकोण से कैसे काम करता है। सबसे पहले, यह अनिवार्य करता है कि बैंकनोटों को जारी करने का काम एक अलग निर्गम विभाग द्वारा किया जाए, जो बैंकिंग विभाग से पूरी तरह से अलग हो, जिसकी संपत्ति का उपयोग केवल अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, निर्गम विभाग की आस्ति और देयताओं को बैंक के अन्य परिचालनों से पूरी तरह से अलग रखा जाता है। दूसरे, यह अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि बैंक के अधिशेष का प्रबंधन कैसे किया जाना है। एक बार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, मूल्यह्रास, कर्मचारी लाभ और अन्य मानक बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए प्रावधान किए जाने के बाद, बचा हुआ अधिशेष को सरकार को अंतरित किया जाना चाहिए। साथ में, ये प्रावधान इस बात की नींव रखते हैं कि आरबीआई अपनी बैलेंस शीट का प्रबंधन कैसे करता है और अपने वित्तीय परिचालन में पारदर्शिता बनाए रखता है।

लेखांकन में विवेक

[2] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 ,33 और 47।

लेखांकन में विवेक, उचित/बाजार मूल्य पर आस्तियों का पुनर्मूल्यन, अप्राप्त लाभ / हानि के उपचार में परंपरा का अनुशीलन और प्राप्त विनिमय लाभ/हानि की रीकॉगनीशन के लिए एक उसके सुसंगत अनुप्रयोग से परिलक्षित होता है। पिछले कुछ वर्षों में, आरबीआई ने प्राप्त लाभ से आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) के रूप में प्रावधान बनाए हैं। पुनर्मूल्यन खाते, अर्थात निवेश पुनर्मूल्यन खाते, और मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेशों का पुनर्मूल्यन और विदेशी मुद्रा आस्तियों के भारतीय रुपये में परिवर्तन से अवास्तविक लाभ/हानि को दर्शाते हैं।

आरबीआई दैनिक आधार पर पूरे विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यन करता है और परिशोधित मूल्यांकन के लिए कोई हिस्सा नहीं निकालता है। सभी विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण को उस दिन के प्रचलित बाजार विनिमय दरों पर प्रतिदिन भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है, जो सीजीआरए के तहत परिलक्षित होता है। घरेलू प्रतिभूतियां साप्ताहिक आधार पर और प्रत्येक महीने के अंत में भी मार्क-टू-मार्केट होती हैं।

एक विवेकपूर्ण लेखांकन अभ्यास के रूप में, आरबीआई प्रतिभूतियों और स्वर्ण पर अवास्तविक पुनर्मूल्यन और परिवर्तन लाभ को आय के रूप में मान्यता नहीं देता है, लेकिन उन्हें बैलेंस शीट में पुनर्मूल्यन शेष के रूप में दर्शाता है। दूसरी ओर, घरेलू/विदेशी प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यन पर किसी भी अवास्तविक हानि का प्रभार वर्ष के अंत में, जब खातों को अंतिम रूप दिया जाता है, आकस्मिकता निधि में लिया जाता है। पुनर्मूल्यन के तहत विभिन्न शीर्षों के बीच कोई विनिमेयता नहीं है, जिसका अर्थ है कि आरबीआई, किसी भी पुनर्मूल्यन हानि के लिए, निवेश के खाते में विवेकपूर्ण प्रावधान करता है और धनात्मक सीजीआरए शेष के साथ इसे ऑफसेट अथवा इसके उलट, नहीं करता।

इन पहलुओं पर अंतरराष्ट्रीय प्रथा[3] काफी दिलचस्प हैं। कुछ केंद्रीय बैंक अपने पोर्टफोलियो के एक हिस्से को उचित मूल्य पर पुनर्मूल्यन करते हैं, जबकि बाकी को परिशोधन लागत पर रखते हैं। कुछ देशों में, आय विवरण में अवास्तविक लाभ और हानि दर्ज की जाती है, जो वित्तीय प्रदर्शन पर उनके प्रभाव को दर्शाती है। यह सम्मेलन साथी केंद्रीय बैंकरों से इन वर्गीकरणों के लिए विविध दृष्टिकोणों, औचित्य और कार्यप्रणाली को समझने के लिए एक अच्छा मंच होगा।

अधिशेष वियोजन नीति

आरबीआई के पास आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) के तहत एक पारदर्शी, सार्वजनिक और नियम-आधारित अधिशेष वितरण नीति है। 2018-19 में पेश किया गया यह ढांचा एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है।[4] ईसीएफ मानता है कि वास्तविक इक्विटी को मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिमों, ऋण और परिचालन जोखिमों को कवर करना चाहिए जबकि पुनर्मूल्यन संतुलन को बाजार जोखिम को कवर करना चाहिए। आवश्यक प्रावधान करने के बाद, शेष अधिशेष सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। आर्थिक पूंजी ढांचे की शुरुआत के बाद से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 महामारी और उसके बाद वैश्विक मौद्रिक सख्ती जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करते हुए भी निर्धारित स्तरों पर अपने जोखिम बफर को लगातार बनाए रखा है। जैसा कि हम निरंतर सुधार और शोधन के लिए प्रयास करते हैं, ईसीएफ की हाल ही में आंतरिक रूप से समीक्षा की गई थी[5], और जोखिम मूल्यांकन को और अधिक विस्तृत बना दिया गया है।

बैलेंस शीट की सुदृढ़ता

पिछले कुछ वर्षों में विवेकपूर्ण लेखांकन नीतियों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक इक्विटी और पुनर्मूल्यन शेष के रूप में जोखिम प्रावधानों के साथ एक मजबूत और सुदृढ़ बैलेंस शीट है, जो वर्तमान में बैलेंस शीट का क्रमशः 7.5% और 17.4% है। इसलिए, बैलेंस शीट के लगभग 25% की आर्थिक पूंजी के साथ, आरबीआई मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपने सार्वजनिक नीति अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए तत्पर है।

[3] जैसा कि विभिन्न केंद्रीय बैंकों की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों से देखा गया है।

[4] भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, अगस्त, 2019।

[5] आरबीआई का आर्थिक पूंजी ढांचा - ढांचे की आंतरिक समीक्षा, मई 2025।

प्रकटीकरण

केंद्रीय बैंक के प्रकटीकरण को पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उन्हें बाजार के प्रति संवेदनशील जानकारी की उचित गोपनीयता बनाए रखते हुए केंद्रीय बैंक के नीति संचालन और उनके वित्तीय प्रभावों को ठीक ढंग से संप्रेषित करने हेतु पर्याप्त पारदर्शी होने की आवश्यकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ-साथ प्रत्येक लेखांकन शीर्ष के लिए व्यापक और विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक की बैलेंस शीट, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि, चलनिधि परिचालनों और आरक्षित निधि घटकों और स्रोतों में वैविध्य का साप्ताहिक स्नैपशॉट भी प्रकाशित किया जाता है। सूचना का यह नियमित प्रवाह हमारे नीतिगत कार्यों और अर्थव्यवस्था में उभरते रुझानों से संबंधित संवाद में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

केंद्रीय बैंक लेखांकन और प्रकटीकरण में उभरते क्षेत्र

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं केंद्रीय बैंक के लेखांकन और प्रकटीकरण में कुछ उभरते क्षेत्रों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जिनके आने वाले दिनों में और अधिक प्रमुखता मिलने की संभावना है। मैं स्वर्ण की कीमतों में हाल ही में तेज वृद्धि के साथ शुरू करता हूं, जिसने केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर इसके प्रभाव के संबंध में वैश्विक स्तर पर बहुत ध्यान और चर्चा प्राप्त की है। आरबीआई ने लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) स्वर्ण की कीमत के 90% पर स्वर्ण की होल्डिंग्स का पुनर्मूल्यन किया है। हालांकि, स्वर्ण का पुनर्मूल्यन की प्रथाएं अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती हैं और केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट और आय पर स्वर्ण की कीमतों में उच्च उतार-चढ़ाव के प्रभाव पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता होती है।

केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के संभावित प्रभाव का मुद्दा भी बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय शोध और चर्चाओं को आकर्षित कर रहा है। कुछ शोध पत्र[6] ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाए गए सीबीडीसी के लिए डिजाइन विकल्प सीबीडीसी को अपनाने और सीबीडीसी के साथ बैंक नोटों और/या बैंक जमा के संभावित प्रतिस्थापन के संबंध में लोगों के व्यवहार को कैसे आकार दे सकते हैं। इस पर भी चर्चा और बहस हो रही है कि क्या और कैसे यह केंद्रीय बैंक बैलेंस शीट संरचनाओं और चलनिधि संचालन की आवश्यकता को प्रभावित कर सकता है।

इन उभरते पहलुओं के लिए भविष्य में निरंतर जुड़ाव और सहयोग की आवश्यकता होगी क्योंकि केंद्रीय बैंक अपने संबंधित अनुभवों से सीखते हैं। हमें इन क्षेत्रों में मिलकर काम करना चाहिए और अपने अनुभवों और रिसर्च को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए, जिससे हम सभी को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

जैसा कि मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूं, मुझे कहना होगा कि यह सम्मेलन बहुत ही उपयुक्त समय पर आयोजित किया जा रहा है क्योंकि दुनिया भर में केंद्रीय बैंक वीयूसीए दुनिया (अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट) में नेविगेट कर रहे हैं। महामारी के दौरान विविध और व्यापक नीतिगत कार्रवाइयों के साथ-साथ अलग-अलग लेखांकन प्रथाओं के परिणामस्वरूप केंद्रीय बैंकों की रिपोर्ट की गई आय और बैलेंस शीट में भिन्नता आई है। केंद्रीय बैंक के प्रकटीकरण ने नीतिगत कार्यों और अपनाई गई लेखांकन नीतियों के औचित्य को प्रभावी ढंग से जनता को संप्रेषित करने में सक्षम होने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे माहौल में, लेखांकन में विवेक और पारदर्शिता केवल प्रचलित शब्द नहीं हैं, बल्कि वे स्तंभ हैं जिनकी केंद्रीय बैंकों को रक्षा करनी चाहिए।

विभिन्न क्षेत्राधिकारों में लेखांकन पद्धतियों में विविधता कुछ सामान्य लेखांकन सिद्धांतों/प्रथाओं पर केंद्रीय बैंकों के बीच संवाद और ज्ञान साझा करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रस्तुत करती है जो विवेकपूर्ण हैं और पारदर्शिता को और बढ़ा सकते हैं। इससे संबंधित देशों के विधिक ढांचे के भीतर केंद्रीय बैंकों में बेहतर प्रकटीकरण की सुविधा मिल सकती है। मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन विवेकपूर्ण और सुसंगत केंद्रीय बैंक

[6] आईएमएफ वर्किंग पेपर: Central Bank Digital Currencies and Financial Stability: Balance Sheet Analysis and Policy Choices, 11 अक्टूबर 2024; ईसीबी सामयिक पेपर श्रृंखला: केंद्रीय बैंक की लाभप्रदता, जोखिम लेने और पूंजी पर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का प्रभाव, 14 नवंबर 2024।

लेखांकन प्रथाओं को प्राप्त करने की दिशा में एक रचनात्मक और सहयोगात्मक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में केंद्रीय बैंकों के बीच निरंतर जुड़ाव और गहन सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहला कदम होना चाहिए।

सम्मेलन के दौरान आप सभी के सफल विचार-विमर्श और उपयोगी परिणामों की कामना करता हूं।

धन्यवाद।